अमेरिका-भारत रक्षा संबंध

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में अमेरिका के रक्षा सचिव की भारत यात्रा, भारत और अमेरिका के रक्षा समझौतों को मजबूत करेगी।

रक्षा संबंध के बारे में

- पिछले कुछ वर्षों में, अमेरिका-भारत संबंधों में अविश्वसनीय गति आई है, जो मुख्य रूप से उनके रक्षा संबंधों से प्रेरित है।
- विशेष रूप से, उनकी यात्रा ने रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए एक रोडमैप पर एक समझौता किया, जिसे 'क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (iCET)' समझौता कहा जाता है। साथ ही इसे लागू करने सम्बन्धी प्रक्रिया पर बल दिया गया।

हालिया यात्रा के उद्देश्य

- **दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे:** तकनीकी नवाचार और बढ़ता सैन्य सहयोग।
- रक्षा उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप बनाकर द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना।
- दोनों देशों के रक्षा क्षेत्रों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देते हुए सह-विकास और सह-उत्पादन पहलों को बढ़ावा देना।
- 'हिंद-प्रशांत क्षेत्र से परे, रक्षा क्षेत्र में भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच व्यापक औद्योगिक सहयोग को पेश करने का एक मजबूत तर्क भारत में अमेरिकी निवेश का मौजूदा पैमाना है।'

क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (iCET)

इसे मई, 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था।

लक्ष्य : इसका उद्देश्य भारत के अपने आत्मनिर्भरता मिशन और आयात निर्भरता को कम करना है, यह संभावित रूप से अमेरिका-भारत सामरिक संबंधों के व्यापक संदर्भ में अमेरिका को पुनर्स्थापित करता है।

इस पहल का नेतृत्व भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद करेगी ।

यह पहल AI, क्वांटम कंप्यूटिंग , 5जी/6जी, बायोटेक, अंतरिक्ष और सेमीकंडक्टर्स जैसे क्षेत्रों में सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग के बीच संबंध बनाने में मदद करेगी ।

iCET के तहत, दोनों पक्षों ने सह-विकास और सह-उत्पादन के छह फोकस क्षेत्रों की पहचान की है:

नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना ;

रक्षा नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग;

लचीला अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला ;

अंतरिक्ष।

सशस्त्र ड्रोन

- अमेरिकी कंपनी के साथ सशस्त्र ड्रोन सौदे की घोषणा प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान की जा सकती है।

इंडस-एक्स (Indus –X)

- यह नवीन पहल 'इंडस-एक्स' का शुभारंभ किया गया, जो दोनों देशों के बीच रक्षा नवाचार संबंधों को एक नई गति प्रदान करेगा।
- यह 2022 में हस्ताक्षरित यूएस-भारत द्विपक्षीय अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता व्यवस्था पर आधारित है, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में सूचना-साझाकरण और सहयोग को बढ़ाने का वादा करती है।
- इसके अतिरिक्त, अमेरिकी अंतरिक्ष कमान और भारत की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के बीच सहयोग के आधार पर रक्षा अंतरिक्ष आदान-प्रदान में नए क्षेत्रों की पहचान की गई है।

प्रमुख रक्षा भागीदार

- अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित समझौतों के साथ भारत का 'प्रमुख रक्षा भागीदार' (एमडीपी) का दर्जा, अब प्रौद्योगिकी को साझा करने और अधिक निरंतर सहयोग की अनुमति देता है।
- इनसे न केवल भारत को सहयोगी बने बिना संवेदनशील प्रौद्योगिकियों को साझा करने की अनुमति मिली है, बल्कि प्रक्रियात्मक कठिनाईयों या संरचनात्मक अंतरों के कारण बैकस्लाइडिंग को रोकने के लिए प्रभावी तंत्र भी स्थापित हुए हैं।

इंडो-पैसिफिक अनिवार्यता

- भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के तहत 2022 में अमेरिका ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका-भारत की रक्षा साझेदारी को उनके जुड़ाव की आधारशिला के रूप में संदर्भित किया।

चार मूलभूत रक्षा समझौते

2016 से पूर्व अमेरिका के रक्षा भागीदार का दर्जा भारत को प्राप्त नहीं था, 2016 के बाद 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए –

लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट (Logistics Exchange Memorandum of Agreement-LEMOA)- वर्ष 2016

भारत-अमेरिका सामरिक ऊर्जा भागीदारी (वर्ष 2017 में घोषित)

संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (Communications Compatibility and Security Agreement -COMCASA)-वर्ष 2018

बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA) – यह भारत को अमेरिकी भू-स्थानिक खुफिया जानकारी तक वास्तविक समय में पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा।

- इसमें पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पर कार्रवाई ; यूक्रेन के प्रति रूस की आक्रामक कार्रवाइयों की सीमाओं को पुनः खींचना; आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बल दिया गया।
- इस क्षेत्र में दोनों देशों द्वारा संयुक्त खतरे के रूप में चीन को इंगित किया गया।
- अमेरिका की चीन सैन्य शक्ति पर रिपोर्ट - 2022, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के अधिक विवादित होने के साथ, चीन की उपस्थिति भारतीय और प्रशांत महासागरों में बढ़ने की संभावना है।
- इंडो-पैसिफिक के रक्षा क्षेत्र कंपनियों के बीच व्यापक औद्योगिक सहयोग को मजबूत करना।
- अमेरिका-भारत रक्षा ने तीन प्रमुख प्रवृत्तियों को जन्म दिया है:
- कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यमों के एक पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण और विकास; अमेरिका भारतीय रक्षा निर्माण में वृद्धि और दोनों पक्षों द्वारा सह-विकास और सह-उत्पादन में बाधाओं को दूर करना।
- बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, बीएई सिस्टम्स, हनीवेल एयरोस्पेस, रेथियॉन, टेक्सट्रॉन और अन्य के नेतृत्व वाली अमेरिकी कंपनियां भारत की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और टाटा समूह की भागीदार हैं।